कारियों के संघ द्वारा वस्त्र मंत्री जी को दिये गये ज्ञापन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) इस मामले के कब तक निपटाये जाने की संभावना है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन॰टी॰सी॰) मिलों के तकनीकी एवं अधिकारी स्टाफ संघ (गुजरात) से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार किया गया था। सरकार ने एन.टी.सी. के सभी सहायक निगमों मे तकनीकी और पर्यवेक्षी स्टाफ के वेतनमानों में एकरूपता लाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक संयुक्त समिति गठित कर दी है। हालांकि संयुक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट निकट भविष्य में ही प्रस्तुत किये जाने की संभावना है, किन्तु इसके लिये ठीक-ठीक समय-समीक्षा बता पाना संभव नही होगा कि एन.टी.सी. के सहायक निगमों के, जिसमें एन.टी.सी. (गुजरात) भी शामिल है, तकनीकी और पर्यवेक्षण संबंधी स्टाफ के वेतनमानों पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा।

देश में बन्द पड़ी कपड़ा मिलें

312. श्री मोर्जा इर्शादबेग : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कितनी कपड़ा मिले चलायी जा रही है तथा उसमें से कितनी मिलें इस समय बन्द पड़ी हैं, तथा उन्हे पुन: आरम्भ करने के संबंध में सरकार की क्या योजना है ; और

(ख) इन मिलों के बन्द हो जाने से कितने कामगार बेकार हो गये हैं तथा उन्हें काम पर लगाने तथा उनकी मदद करने के संबंध में क्या योजनायें आरम्भ की गयी हैं तथा उसके लिये क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

वस्त्र मंत्री और साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन 124 मिलें तथा ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के अधीन 2 कपड़ा मिलें हैं, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन 124 कपड़ा मिलों में से 2 मिलें जो 1974 में राष्ट्रीयकरण के समय बन्द हो गयी थीं, मशीनों की खराब स्थिति के कारण पुन: चालू नही की जा सकी। ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के अन्तर्गत आने वाली सभी मिलें इस समय चालू हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरदार सरोवर परियोजना

313. श्री मोर्जा इर्शादबेग : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च हुई है तथा प्रयोजनार्थ किये गये वित्तीय आवंटनों का ब्यौरा क्या है ; तथा इस परियोजना के संबंध में विश्व बैंक का विचार क्या है ; और

(ग) गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा इस संबंध में कितनी प्रगति की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) लगभग 1000 करोड़ रुपये के वितरण प्रणाली सहित बांध पर मुख्य कार्य, नहर, विद्युत-गृह का निर्माण चल रहा है। 1000 करोड़ रुपये की लागत के कार्यों के लिये संविदायें देने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। अक्तूबर, 1989 तक 726.32 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं। वर्ष 1989–90 के लिये आवंटन 250.10 करोड़ रुपये था। दिसम्बर, 1989 मे

विश्व बैंक मिशन द्वारा अपने दौरे के दौरान विभिन्न मदों तथा कार्यों की कोटि की प्रगति पर समग्र संतुष्टि व्यक्त की गयी है।

Additional grant recommended by the 9th Finance Commission for improvement of slums in Maharashtra

314. SHRI VASHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the additional grant of Rs. 50 crores as recommended by the Ninth Finance Commission for improvement of slums has since been sanctioned to the Government of Maharashtra;

(b) if so, what are the names of the projects proposed to be undertaken to utilise this grant; and

(c) whether Government propose to sanction additional funds for the development of Bombay only?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) to (c) The Ninth Finance Commission has recommended in its First Report for 1989-90 a grant of Rs. 50 crores to the Government of Maharashtra for slum clearance and environmental improvement of slums and provision of basic amenities in the city of Bombay with an equal matching contribution by the State Government.

The State Government have proposed a number of schemes for improvement and provision of amenities and services in slums in Bombay *viz.*, housing, water supply, drainage and sanitation facilities, relocation and resettlement of slums, construction of roads, bridges and sub-ways, upgrading and improvement of health and hospital facilities, development of transport and electricity supply, traffic management, etc., with a total outlay of Rs. 138.74 crores (which will be limited to Rs. 100 crores for the purpose of utilising the above mentioned grant). Of this, schemes with an outlay of Rs. 97.55 crores have so far been approved and a grant of Rs. 12.19 crores has been released.

Besides the above, a special non-Plan grant of Rs. 100 crores is being provided to the Government of Maharashtra for slum upgradation and housing in Bombay. Of this Rs. 50 crores have so far been released to the State Government.

Prosecution under various economic offences

315. SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of the leading industrialists/companies prosecuted for violation of FERA provisions evasion of excise duty income-tax during the last three years; and

(b) the progress made so far relating to these cases?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) During the last three years, the Central Excise Authorities prosecuted 8 leading industrialists/companies for violation of Central Excise Laws. No prosecution has been launched against any of the leading industrialists/companies for violation of FERA during this period. Income-tax Department launched 721 prosecusions Department launched 721 prosecutions during 1988-89, 562 prosecutions during 1987-88 and 1426 prosecutions during 1986-87.

(b) All the above cases are pending in the courts of law at various stages.

Alleged opening of account in First Trust Corporation of St. Kitts, West Indies by certain individuals

316. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) wheher Government have issued instructions to the CBI or any other investigating agency to investigate into the alleged opening of account in First Trust Corporation of St. Kitts, West Indies ISI by certain individuals;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether any officials of the CBI or any other investigation agency of the